नॅशनल एसोसिएशन ऑफ़ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ़ इंडिया

राष्ट्रीय सम्मेलन और वार्षिक आम बैठक

स्ट्रीट विन्डिंग एक्ट 2014 के बाद भारत में स्ट्रीट वेंडिंग: संभावनाएँ और चुनौतियाँ

सर पुत्तन्ना शेट्टी टाउन हॉल, बेंगलुरु

6 -7 सितंबर, 2019

स्ट्रीट वेंडर भारतीय शहरों का एक महत्वपूर्ण खंड बनाते हैं क्योंकि वे बेहतर लागत और सुविधाजनक स्थानों पर सामान और सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त , स्ट्रीट वेंडिंग शहरों में रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा कर रही है। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम) के तहत , भारत सरकार स्ट्रीट वेंडिंग की सुरक्षा और स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए 5% फंड प्रदान करती है। स्ट्रीट वेंडर अपने परिवारों की देखभाल के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। यह गरीबों के लिए उद्यमशीलता सीखने और गरीबी दूर करने के लिए एक अच्छा विकल्प है।

- **स्ट्रीट वेंडर के सामान और सेवाएं बेहतर लागत और सुविधाजनक स्थानों पर हैं- उन्हें स्ट्रीट वेंडर्स अधिनियम और नियमों के तहत विनियमित किया जाना चाहिए।**
- **विक्रेताओं को आत्मनिर्भर उद्यमियों के रूप में मान्यता दी जाय।**
- **400 शहरों के 700 प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया।**

इस सम्मेलन में 500 शहरों के स्ट्रीट वेंडर्स के 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसका उद्घाटन श्रीमती गंगाम्बिक मल्लिकार्जुन महापौर, बीबीएमपी, कर्नाटक द्वारा श्री राजेश वर्मा, महापौर भागलपुर, बिहार, श्री शंता कुमार, राष्ट्रीय सचिव, आईएनटीयूसी, नासवी अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में किया गया। कन्वेंशन और एजीएम को फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफ्टंग (एफईएस) , अदिति, निधि, सेल्फ वर्कर ग्लोबल , कर्नाटक स्ट्रीट वेंडर फेडरेशन और कर्नाटक प्रदेश लेबर कोऑर्डिनेशन कमेटी का समर्थन प्राप्त था।

गणमान्य द्वारा कन्वेंशन का उद्घाटन

मेयर बीबीएमपी, श्रीमती गंगाम्बिक मल्लिकार्जुन ने बताया कि विक्रेताओं को वेंडिंग के लिए एक अलग स्थान दिया जाएगा। बंग्लुरु मेट्रोपॉलिटन सिटी के 8 क्षेत्रों में, सड़क विक्रेताओं को फुटपाथों पर बसाया जाएगा, हालांकि यह भी ध्यान रखा जाएगा कि पैदल चलने वालों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। हम इस योजना पर काम कर रहे हैं। बैंगलोर में 80000 स्ट्रीट वेंडर हैं, जिनमें से 24000 को पहचान पत्र दिए गए हैं। उचित रोजगार न मिलने की स्थिति में फुटपाथ पर व्यवसाय करना कहीं से भी अपराध नहीं है।

श्री एचटी संगलियाना (आईपीएस) , पूर्व महानिदेशक, आईजी और एमपी ने बताया कि स्ट्रीट विक्रेताओं को बीमा, आवास सुविधा, स्वास्थ्य योजना और अन्य सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता है। कई बार स्ट्रीट वेंडरों को नगर पालिका और पुलिस विभाग के कर्मचारियों द्वारा परेशान किया जाता है। इन विक्रेताओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा जाना चाहिए। हम देखते हैं कि हर शहर में, खुदरा विक्रेता चिंतित हैं। नासवी को हर जगह संगठन विकसित करना चाहिए।

कर्नाटक सरकार के पूर्व गृह मंत्री, श्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि फुटपाथ व्यापारियों की समस्या को हल करने के लिए इस पर चर्चा की जानी चाहिए। एक महासंघ के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से मिलना होगा। यदि किसी व्यवसायी को नगरपालिका या पुलिसकर्मी द्वारा परेशान किया जाता है , तो संबंधित क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त से शिकायत करें। सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए सभी फुटपाथ दुकानदारों को एकजुट होना चाहिए।

सुश्री सुमति (केएमएएस) परियोजना अधिकारी, डे एनयूएलएम, कर्नाटक ने सम्मेलन को बताया कि राज्य सरकार स्ट्रीट विक्रेताओं तक पहुँचने के लिए प्रतिबद्ध है। नियमों को अधिसूचित किया गया है और बहुत जल्द योजनाओं को राज्य द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। हम प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय में टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हम स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दे पर सड़क विक्रेताओं को कौशल विकास प्रशिक्षण से भी जोड़ रहे हैं।

श्री मुथुमरण -क्षेत्रीय निदेशक, एफएसएसएआई, भारत सरकार ने "न्यू फ्रंटियर्स इन स्ट्रीट वेंडिंग" सत्र के तहत संबोधित किया। उन्होंने एफएसएसएआई प्रशिक्षण प्रक्रिया और प्रशिक्षण की आवश्यकता के बारे में बताया।

सुश्री सोम्या रेड्डी , विधायक, जयनगर ने अपने अनुभव को साझा किया क्योंकि पुलिस विक्रेताओं की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करती है और सरकार सड़क विक्रेताओं की समस्याओं को हल करने में विफल रही है।

सुश्री दमयंती श्रीधरन , वरिष्ठ सलाहकार , फ्रेडरिक एबर्ट स्टिफंग (एफईएस) ने सम्मेलन को संबोधित किया और महिला सड़क विक्रेताओं के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया।

श्री राजेश वर्मा, उप निदेशक महापौर, भागलपुर, ने भागलपुर में वेंडिंग के विनियमन पर अपने अनुभव को साझा किया क्योंकि बीएमसी ने सड़क के किनारे 57 वेंडिंग जोन बनाए।

श्री शांता कुमार, राष्ट्रीय सचिव, आईएनटीयूसी

नासवी के अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश सिंह ने थ्री-ई -अर्थव्यवस्था, रोजगार और उद्यमिता पर प्रकाश डाला

श्री श्वेतांक मिश्रा, पॉल हेमिलिन फाउंडेशन विक्रेताओं के बीच क्षमता निर्माण और नेतृत्व संवर्धन सत्र के तहत बोलते हुए।

अदिति की कार्यकारी सचिव , सुश्री असिता माल्धी यार ने समुदाय के बीच नेतृत्व संवर्धन पर अपने अनुभव को साझा किया

श्री वेद प्रकाश दयाल , राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन , बिहार सामाजिक अर्थव्यवस्था को सत्र के तहत बढ़ावा देते हुए।

श्री अरविंद सिंह, समन्वयक, नासवी सम्मलेन में एजेंडा प्रस्तुत करते हुए।

नासवी के ने शनल को-ऑर्डिनेटर, श्री अरबिंद सिंह ने कहा कि भारत में एक ऐसा मामला है जिसमें एक प्राधिकरण दूसरे को दोषी ठहराते है और स्ट्रीट वेंडर हमेशा सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम , 2014 - अधिनियम के 3 (3) के तहत, "कोई भी सड़क विक्रेता बेदखल नहीं किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो, सब-सेक्शन 1 के तहत निर्दिष्ट सर्वेक्षण पूरा न हो जाए तब तक स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है और सभी स्ट्रीट वेंडर्स को वेंडिंग का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है "।

नासवी के अध्यक्ष, श्री चंद्रप्रकाश सिंह ने सुझाव दिया कि नासवी को ट्रिपल ई पर एक अभियान शुरू करना चाहिए क्योंकि वेंडर तीन ई - अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देते हैं विशेष रूप से स्थानीय अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर योगदान द्वारा , उद्यमिता क्योंकि वे गरीबी से बाहर आने के अच्छे उदाहरण हैं और रोजगार को कम कर रहे हैं और सरकार पर बढ़ते सरकारी नौकरियों के बोझ को कम कर रहे हैं। हालांकि, वे माफियाओं से पीड़ित रहते हैं और नगरपालिका एंटीपायथी के नियम का पालन करते हैं। स्ट्रीट वेंडर कोर्ट जाने के एकमात्र विकल्प के साथ बचे हैं , जो संभवतः अधिक खर्च भी नहीं कर सकते हैं। न्यायालय कुछ राहत दे रहे हैं लेकिन यह एक अच्छा विषय नहीं है।

विभिन्न शहरों के सदस्यों ने कहा कि देश में 20 मिलियन स्ट्रीट वेंडर जिनकी आजीविका केवल वेंडिंग पर निर्भर हैं। शहर के गरीब और मध्यम वर्ग को सड़क विक्रेताओं से कम मूल्य पर सामान प्राप्त करने से लाभ होता है। यह निश्चित है कि शहर के लाखों लोग स्ट्रीट वेंडर के काम से लाभान्वित होते हैं। कानून के अनुसार, सड़क विक्रेताओं को अपराधियों या भिखारियों के रूप में नहीं माना जाता है, बल्कि, उन्हें सम्मानजनक और आत्मनिर्भर उद्यमियों के रूप में पहचाना जाता है। यह सम्मलेन स्ट्रीट वेंडिंग में न्यू फ्रंटियर्स, प्रमोटिंग सोशल इकोनॉमी, क्षमता निर्माण और स्ट्रीट वेंडर्स के बीच लीडरशिप प्रमोशन आदि सत्रों में बटा हुआ था।

श्री रंगास्वामी , बीड़ी बदी व्यपारी संघटन के अध्यक्ष , और श्री बयप्पना हल्ली रमेश कर्नाटक, राज्य श्रम समन्वय समिति बंग्लुरु ने संयुक्त रूप से इस सम्मेलन के माध्यम से एक मांग पत्र रखा :

- जिन विक्रेताओं को बेंगलुरु में पहचान पत्र और प्रमाण पत्र दिया गया है, उन्हें पुलिस द्वारा परेशान नहीं किया जाना चाहिए।
- कर्नाटक सरकार शीघ्र अधिनियम की धारा 38 के तहत अनिवार्य रूप से इस योजना को घोषित करे
- अधिनियम, विशेष रूप से अनुभाग 3.3 जिसके तहत एक विक्रेता को सर्वेक्षण से निष्कासन के खिलाफ संरक्षित किया जाता है, लाइसेंस दिया जाता है और उसे स्थान दिया जाता है उसमें तत्काल प्रवर्तन लाये
- परिपत्र जारी करने के दो महीने के भीतर राज्यों में विवाद निवारण तंत्र के गठन के लिए सख्त परिपत्र जारी करें।
- स्ट्रीट वेंडिंग के सभी पहलुओं के बारे में निर्णय लेने के लिए अधिनियम द्वारा शासित टाउन वेंडिंग कमेटी (TVC) की नियमित बैठकें करे
- स्ट्रीट वेंडर्स के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के 5% खर्च में तेजी लाये
- टीवीसी सदस्यों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन

Street vendors to press for rights at convention in city

Bengaluru is falling behind in providing for its street vendors

APEKSHA M
BENGALURU, DHNS

The mayor will inaugurate the event, aimed at establishing a dialogue between vendors and authorities. DH FILE PHOTO

Street vendors and their representatives from across the country will gather in Bengaluru on Friday to press for their rights at a national convention.

As many as 800 street vendor representatives are expected to take part in the convention being organised by the National Association of Street Vendors of India (NASVI).

Mayor Gangambike Mallikarjun will inaugurate the two-day event, which is aimed at establishing a dialogue between vendors and authorities.

Arbind Singh, national coordinator and founder of NASVI, told *DH* that the conference will discuss measures needed to protect street vendors' interests.

"We will urge the Karnataka government to implement the 'Badavara Bandhu' scheme, establish marked vending zones and set up Town Vending Committees (TVCs) to provide street vendors an established body," Singh said.

Rangaswamy, leader of state vendors association, pointed out the shortcomings in the government scheme.

"Karnataka has around 4.5 lakh vendors, but only 1.8 lakh vendors have been identified by the government. In Bengaluru, they have surveyed about 25,000 vendors, but only 15,000 have received identity cards," he said.

Rakesh Tripathi, the senior program manager of NASVI, highlighted the poor implementation of the Street Vendors Act of 2014.

"The situation is poor in every state. Vendors do not have enough space and are harassed by the police. Delhi has formed TVCs, but it doesn't function properly. Telangana has only three vending zones and Varanasi has identified only 250 vendors of its 25,000 vendors," he said.

However, Bengaluru is falling behind in providing for its street vendors when compared to other metropolitan cities. "The situation is better in cities like Patna, which has a 2 km-long hawker zone. We want the same thing in Bengaluru," said Rangaswamy.

BBMP Mayor Gangambike Mallikarjuna inaugurated National Convention Association of Street Vendors of India at Town Hall in Bengaluru on Friday. former MP HT Sangliyana, Former Minister Ramalinga Reddy, Coordinator of Nation Association of Street Vendors of India Arbind Singh, Member of Karnataka Beedhi Badhi Vyapari Sanghatane Rangaswamy and others are seen —*KPN*

3Rs: State kids fare poorly, says report

VISHAKA V
WARRIER | DC
BENGALURU, SEPT. 6

The reading and comprehending abilities of children in Karnataka is so alarmingly poor that students of the higher classes are not able to read and comprehend texts of their sub-juniors, reveals the Annual Status of Education Report, 2018 for the state.

While the sampling is predominantly from the rural parts of the state, the trend is similar among urban children covered too. The study in rural areas was done in both government and private schools.

Worryingly, the report says that 80.8 per cent of children in the third standard cannot read or comprehend texts belonging to the class 2 children. "As many as 54.0 per cent children in the fifth grade cannot read the texts of the second grade and 29.7 per cent of children in the eighth grade cannot read texts of the second grade," it reveals.

> This data highlights the poor reading abilities of children in the rural parts of Karnataka, the picture is almost identical in the urban parts as well. The study is clearly a wake-up call to the education sector to address the issue of reading disabilities among children.

While this data highlights the poor reading abilities of children in the rural parts of Karnataka, the picture is almost identical in the urban parts as well. The study is clearly a wake-up call to the education sector to address the issue of reading disabilities among children.

One of the problems appears to be that while schools that cater to the privileged sections of society have libraries, those that cater to the underprivileged either don't have one or don't have ones that are functional.

And although the government has established the Indira Priyadarshini Childrens' Library, few children visit it. The issue is complex as reading is seen as a luxury among parents from a poor economic background, who don't find buying a storybook for their children a necessity.

Ms Shahnaz Sultana, adjunct faculty, mechanical department, PES University and co-founder of 'Reading Stars India' says she was shocked to find during her sessions on personality development for high school children that they found it very difficult to read and understand the written word.

On inquiring, she learnt that the children were used to rote learning and didn't even read their textbooks. "I was disturbed as they scored good marks with rote learning while they couldn't actually read properly. We then approached schools and community centres to encourage reading among children," she explains. The initial problem that she encountered was the drastic reading disability among children as against their grades. To address this, the children were introduced to a Library Readiness Programme, which was adopted from a system followed in the USA.

"Based on research, 'Dolch Words' were constructed where over 300 words which covers 50 per cent of words used upto class 5, were identified and taught using creative means to children.

नेशनल एसोसिएशन आफ स्ट्रीट वेंडर ऑफ इंडिया की वार्षिक साधारण सभा

बरगढ़. विगत 6 एवं 7 सितम्बर को बैंगलुरु स्थित टाउन हाल में नेशनल एसोसिएशन आफ स्ट्रीट वेंडर आफ इन्डिया (नासवी) की वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया. सभा में स्थानीय विधायक, नगरपालिका कार्पोरेशन के मेयर, नासवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश सिंह, सचिव अरविन्द, भारत के सभी राज्यों से आये 500 से भी अधिक कार्यकर्ता उपस्थित थे. ओड़िशा से राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रीतम सिंह, ओड़िशा प्रदेश अध्यक्ष महेश्वर बल, सचिव श्रीमती सुजाता साहू सहित 40 सदस्यों ने इस सभा में उपस्थिति दर्ज कराई. सभा में केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में पास किये गये स्ट्रीट वेन्डर एक्ट को सभी राज्यों में लागू करने, अस्थायी दुकानदारों को स्थायी करने की व्यवस्था तथा उनकी सुरक्षा एवं परिवार एवं बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था पर चर्चा की गई. सरकार यदि इस ओर कोई समाधान नहीं करती है तो तुरन्त इसके विरोध में राष्ट्रीय स्तर पर आन्दोलन किये जाने पर चर्चा की गई.

ಬೀದಿಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯ
ಗುರುತಿಸಲು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಚಿಂತನೆ

Street vendors to meet to bat for their rights

Their major concerns in Bengaluru and Karnataka as a whole specifically is the non-implementation of the Town Vending Committee (TVC) in every municipal corporation as mandated by the Act.

Published: 06th September 2019 06:45 AM | Last Updated: 06th September 2019 06:45 AM

By Express News Service

BENGALURU: In order to push for implementation of the Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act 2014, the National Association of Street Vendors of India (NASVI) will be holding a two-day conference in the city from September 6.

Their major concerns in Bengaluru and Karnataka as a whole specifically is the non-implementation of the Town Vending Committee (TVC) in every municipal corporation as mandated by the Act.

"The TVC is responsible for issuing ID cards, vending certificates to street vendors and finalising vending zones in the city. They have not constituted the TVC in any of the state's municipal corporations.

We surveyed and found 24,300 vendors in Bengaluru of which only 15,000 have been given the ID cards and certificates. The TVC also has to make proper vending zones in the city," said Bhaskar, vice-president, NASVI.

"Our demands include stopping the harassment of vendors who have the required documents," he added.

Arbhind Singh, president, NASVI, said, "Our other demands include setting up of a grievance redressal cell."

'ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಲಯ' ರಚನೆಗೆ ಚಿಂತನೆ

निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

• टीवीसी के विभिन्न निर्णयों को समझने के लिए वेंडर नेताओं को धरना प्रदर्शनों से परे जाना चाहिए ताकि उनका उचित पालन हो सके

• युवा नासवी की शुरुआत की जानी चाहिए

• वर्तमान स्वास्थ्य कार्यक्रमों या स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन के साथ मिलकर स्वास्थ्य क्षेत्र में हस्तक्षेप किया जाना चाहिए

• बच्चों के लिए बाजार में शैक्षिक सुविधाओं का आयोजन किया जाना चाहिए

• नासवी को पर्यटन केंद्रों में विक्रेताओं के प्रचार के लिए पर्यटन मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहिए

- **समन्वयक रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और अपनाई गई**
- **खातों के आंतरिक नियंत्रण से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए**

- देश में स्थिति इतनी भयावह है कि विक्रेताओं के लिए केवल करो या मरो का विकल्प है
- रेलवे विक्रेताओं के मुद्दों में विशेष रूप से उन महिला विक्रेताओं का उठाया जाना चाहिए जो अन्य स्थानों से सामान खरीदती हैं और उन्हें बेचने के लिए ट्रेन में ले जाती हैं
- वेंडर नेताओं को वास्तव में शहरी स्तर के कारणों पर वकालत करनी चाहिए और अपने लाभों के लिए मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए है
- नासवी को माइक्रो फाइनेंस पर भी ध्यान देना चाहिए और इसके लिए एक कंपनी शुरू करनी चाहिए
- आंध्र प्रदेश जैसे कम सदस्यता वाले राज्य पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए सरकार को हिला देने के लिए बड़ा आयोजन किया जाना चाहिए।
- जिन नेताओं का निधन हो चुका है, उन्हें पहचाना जाना चाहिए और उन्हें याद किया जाना चाहिए और जो नेता सक्रिय नहीं हैं उन्हें भी शामिल करना चाहिए।
- नासवी को स्थानीय स्तर पर कार्यालय खोलने के लिए दिशानिर्देश जारी करना चाहिए ।
- नासवी का एक कैलेंडर प्रकाशित किया जाना चाहिए ।
- विक्रेताओं को अपने मुद्दों को उजागर करने के लिए एक पोस्टकार्ड अभियान करना चाहिए।
- अच्छे नेताओं को सम्मानित किया जाना चाहिए।
- सभी विक्रेता नेताओं को ट्विटर सहित सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- विक्रेता नेताओं को नासवी कार्यालय में अपने संबंधित संपर्क व्यक्ति को जानना चाहिए।
- नासवी को सभी स्तरों पर अधिकारियों को लिखना चाहिए
- विक्रेताओं को भी "नो सिंगल यूज़ प्लास्टिक" अभियान में शामिल होना चाहिए।
- टीवीसी के लिए नए प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए जाने चाहिए।
- बेंगलुरु में एक दक्षिणी क्षेत्रीय कार्यालय को विकसित करना चाहिए
- वेंडर द्वारा सोलर लाइट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए
- नासवी को स्मार्ट सिटी के बजाय रोजगार सिटी को बढ़ावा देना चाहिए
- स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम के कार्यान्वयन पर ध्यान दिया जाना चाहिए
- स्ट्रीट वेंडिंग को अपनी सीमा को बढ़ाना चाहिए जैसे कि एप्स, होम डिलीवरी पद्धति, सुंदर वेंडिंग जोन इत्यादि
- वर्तमान नेताओं को दूसरी पंक्ति का नेतृत्व विकसित करना होगा
- संगठनों को बनाये रखने के लिए एक समुदाय आधारित राजस्व मॉडल विकसित हुआ
- ट्रिपल ई - इकोनॉमी, इम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइज, अब नासवी का मंत्र होना चाहिए